सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें

फोनः 0141-2202717

मोः 9214203182

वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-267 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, रविवार 01 जून , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में

नारी शक्ति को मिली सौगातें

जयपुर। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर को समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है, उन्होंने संस्कृति एवं विरासत को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। उन्होंने जीवन में महिला उत्थान को ही अपना लक्ष्य माना। नड्डा ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तीकरण के साथ महिला-नेतृत्व विकास की ओर बढ़ रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नड्डा शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तीकरण महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होल्कर के आदर्शों से प्रेरणा लेकर उनकी 300वीं जयंती पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिला शिक्षा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को महिला शक्ति को समर्पित किया है। उन्होंने राज्य सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना को लिंगानुपात सुधार एवं गर्भ की पाठशाला योजना को महिला

स्वास्थ्य की दिशा में अच्छी पहल बताया।

वर्ष 2014 के बाद बदली देश की तस्वीर

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश की तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व ने राजनीति की संस्कृति को बदलने का काम किया है। अब दोषारोपण के बजाए समाज के हर वर्ग का सशक्तीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जबावदेहिता और उत्तरदायित्व को राजनीति की परिभाषा बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार दिन-रात जनसेवा में जुटी हुई है।

हॉलिस्टिक एप्रोच के साथ नई स्वास्थ्य नीति लागू

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में हॉलिस्टिक एप्रोच के साथ नई स्वास्थ्य नीति लागू की गई है। इसमें निवारण से लेकर पुनर्वास को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 30 वर्ष की उम्र से ही कैंसर, डायबिटीज जैसे गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ उपलब्ध करवाते हुए 1 लाख 77 हजार आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत 64 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राजस्थान में 3 हजार करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। देश में 23 एम्स संस्थान संचालित किए जा रहे है। राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत देश के 63 करोड़ लोगों को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।

देवी अहिल्याबाई ने सामाजिक सुधारों को दिया बढ़ावा- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि 18वीं सदी में देवी अहिल्याबाई जी अपने साहस एवं बुद्धिमत्ता से नारी शक्ति की प्रतीक बनीं। उन्होंने महिला शिक्षा, धर्म, और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, सोमनाथ मंदिर और देशभर में अनेक तीर्थस्थलों का जीर्णोद्धार उनके धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान का प्रतीक है।

जेपी नड्डा ने बताया क्यों बने भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री

जयपुर । बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर बड़ा खुलासा किया है । जयपुर में बीजेपी ने कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने बताया क्यों बने भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ।

नड्डा ने कहा कि कहा यह

विचारधारा के सच्चे सिपाही हैं, जो दिन-रात मोदी जी के विजन को जन-जन तक पहुंचा रहे हैं । उन्होंने कहा कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है । वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा आपने देखा है कि पहले सरकारें कैसे चलती थीं, उनकी सोच क्या थी – सबके सामने है दिन और रात का फर्क हो तो दिन को पसंद करना चाहिए – यही अंतर हमारी और उनकी सरकार में है। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा हमारी सरकार जनसेवा के लिए काम करती है, ना कि स्वार्थ के लिए।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का लगाया आरोप

संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया।

यह बयान सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (ष्टष्ठस्) जनरल अनिल चौहान के एक साक्षात्कार के बाद आया, जिसमें उनके बयानों ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क पर कहा कि ष्टष्ठस् के बयान से कई सवाल उठे हैं, जिनके जवाब के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए।

उन्होंने विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद की सैन्य कार्रवाइयों, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, पर चर्चा की मांग की।

क्या युद्धविराम देश के हित में था- खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर पारदर्शिता नहीं बरत रहे और युद्धविराम (सीजफायर) की शर्तों को स्पष्ट नहीं कर रहे। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह युद्धविराम देश के हित में था। इसके अलावा, खरगे ने कारगिल युद्ध की तर्ज पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की, जो इन घटनाओं की गहन समीक्षा करे।

ट्रंप ने सीजफायर कराने के दावे को फिर दोहराया

एक्स पर पोस्ट करते हुए खरगे ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम कराने के अपने दावे को फिर दोहराया है।

यह शिमला समझौते का सीधा अपमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बार-बार किए गए दावों और अमेरिकी वाणिज्य सचिव द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में दायर हलफनामे को स्पष्ट करने के बजाय, पीएम मोदी चुनावी तूफान में हैं।

'व्यक्तिगत श्रेय ले रहे पीएम मोदी'

उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी हमारे सशस्त्र बलों की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं, उनकी बहादुरी के पीछे छिप रहे हैं और सहमत युद्ध विराम की रूपरेखा को चकमा दे रहे हैं, जिसकी घोषणा विदेश सचिव ने 10 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद की थी।

TMC ने विशेष सत्र की मांग का किया था समर्थन

बता दें कि विपक्षी दलों, जैसे तृणमूल कांग्रेस (TMC), ने भी पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विशेष सत्र की मांग का समर्थन किया है। TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने खुफिया विफलताओं की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने की बड़ी कार्रवाई

सीकर। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर एंटी करप्शन ब्यूरो (ष्टष्ठक) ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला सीकर में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. दीपक अग्रवाल को आज 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई एसीबी स्पेशल यूनिट द्वितीय, जयपुर द्वारा की गई। शिकायत से गिरफ्तारी तक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉ. रविप्रकाश मेहरडा ने जानकारी देते हुए बताया कि ष्टष्ठकको एक परिवादी से शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी अधिकारी डॉ. दीपक अग्रवाल परिवादी से उसके पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से मासिक बंधी के रूप में रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, इच्छित स्थान पर तबादला करवाने के एवज में भी पैसे की मांग की जा रही थी।

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस (चतुर्थ) श्री अनिल कयाल के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर प्रसाद के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। सत्यापन के बाद योजना बनाकर ट्रैप की कार्रवाई की गई।

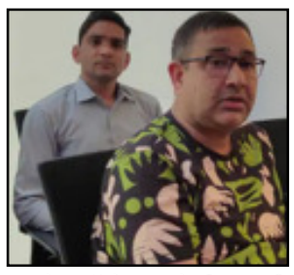

ट्रैप ऑपरेशन और गिरफ्तारी

दिनांक 31 मई को ष्टष्ठकटीम ने जाल बिछाया और आरोपी डॉ. दीपक अग्रवाल को परिवादी से 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई सीकर जिले में पशुपालन विभाग के कार्यालय परिसर में की गई। टीम ने मौके से रिश्वत की राशि भी जब्त कर ली है।

अभी जारी है पूछताछ और अनुसंधान

गिरफ्तारी के बाद आरोपी अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। ष्टष्ठक अधिकारियों के अनुसार, यह भी जांच की जा रही है कि रिश्वतखोरी का यह कोई एकल मामला था या विभाग में इससे जुड़े अन्य अधिकारी भी संलिप्त हैं। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि यह कोई पहली बार की गई रिश्वत नहीं थी बल्कि एक मासिक बंधी प्रणाली के तहत लगातार की जा रही वसूली का हिस्सा थी।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

एसीबी द्वारा आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आगे की पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है। डॉ. अग्रवाल के मोबाइल, दस्तावेज़ और अन्य संदिग्ध लेन-देन की जांच की जा रही है।

प्रशासन और सरकार की चुप्पी

इस मामले पर अभी तक पशुपालन विभाग या राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालाँकि, एसीबी की यह कार्रवाई साफ़ संकेत देती है कि सरकार प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है।

स्थानीय स्तर पर हलचल

सीकर में हुई इस गिरफ्तारी के बाद पशुपालन विभाग और अन्य सरकारी विभागों में हलचल मच गई है। आम नागरिकों और कर्मचारियों के बीच चर्चा है कि अगर ऐसे बड़े पद पर बैठा अधिकारी रिश्वतखोरी में लिप्त हो सकता है, तो नीचे के स्तर पर क्या स्थिति होगी।

ACB की लगातार चौकसी

राजस्थान में ष्टष्ठकी सक्रियता हाल के महीनों में काफी बढ़ी है। इससे पहले भी विभिन्न विभागों में उच्च अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। ष्टष्ठक द्वारा चलाए जा रहे अभियान का उद्देश्य सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना है।

भाजपा राज में बेलगाम बजरी माफिया, चरमराई कानून व्यवस्था-डोटासरा

टोंक। राज्य की राजनीति में विपक्ष ने एक बार फिर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने टोंक में अपने दौरे के दौरान मीडिया और जनता को संबोधित करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की बदहाली और अवैध बजरी खनन को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। जयपुर से बूंदी की ओर जाते हुए डोटासरा और जूली का टोंक में जिला कांग्रेस कमेटी टोंक द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। हरिप्रसाद बेरवा के नेतृत्व में पक्का बंधा पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी ने माहौल को राजनीतिक रूप से जीवंत कर दिया। हालांकि, कार्यक्रम का मुख्य केंद्रबिंदु कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोप रहे। राज्य में भाजपा के शासन में अवैध बजरी खनन

खुलेआम चल रहा है। करोड़ों की बजरी माफिया के हाथों में है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने दावा किया कि केवल डेढ़ वर्ष में ही कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार आम जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही और किसान वर्ग सरकार से पूरी तरह नाराज़ है। डोटासरा के अनुसार, राज्य में जनहित के मुद्दों की उपेक्षा हो रही है और प्रशासनिक प्रणाली बजरी माफियाओं के आगे लाचार नज़र आ रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजरी खनन के मुद्दे को और अधिक विस्तार देते हुए कहा- सरकार की मिलीभगत से करोड़ों की अवैध बजरी निकाली जा रही है। राज्य में पेयजल संकट गहराया हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बेहद खराब हैं। जूली ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाए गए थे, जबकि भाजपा सरकार इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि भाजपा के ही कई मंत्री सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे यह साफ है कि भीतरखाने सरकार की विश्वसनीयता डगमगाई हुई है।

इस मौके पर मौजूद प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, पूर्व विधायक कमल बेरवा, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाशी देवी मीणा, और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया। एक ओर जहां मंच से भाजपा सरकार पर हमले हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं।

किरोड़ीलाल मीणा के छापे के बाद कृषि विभाग में मची खलबली, फैक्ट्रियों पर होगा बड़ा एक्शन

जयपुर। राजस्थान के कृषि मंत्री ?डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने अजमेर के किशनगढ़ में नकली उर्वरक की फैक्ट्रियों पर छापा मारकर प्रदेश की जमीन को बंजर बनाने के खेल का पर्दाफाश किया है। मौके पर मिले नकली उर्वरक मानकों पर खरे नहीं उतरे। नकली उर्वरकों में खतरनाक मार्बल स्लरी और जिप्सम पाउडर निर्धारित मानकों से ज्यादा पाए जाने पर राज्य के कृषि विभाग में भी खलबली मच गई। अब विभाग ने संबंधित फैक्टियों के संचालकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। दूसरी तरफ विभाग के इंस्पेक्टर अब क्षेत्र की फैक्ट्रियों से सैंपल लेने की भागदौड़ कर रहे हैं।

अजमेर की मार्बलनगरी किशनगढ़ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार किए जा रहे नकली उर्वरक की सप्लाई देशभर करने की सूचना पर पिछले दो दिन में राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा फैक्टरियों पर छापेमारी की। उनका कहना है कि

इन फैक्टरियों में नामी कंपनी (इफको) के लिए माल तैयार करने के संकेत भी मिले हैं। इस संबंध में कंपनी के अधिकारी को बुलाकर जानकारी ली गई है।

इस नकली उर्वरक पर कंपनी का टैग लगाकर बेचने से ना केवल साख खराब हो रही है बल्कि किसानों के खेत बंजर होने का खतरा भी है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को भी अवगत कराया गया है। इन फैक्टरियों में लाखों टन नकली उर्वरक एवं कच्चा माल सीज किया गया है। यहां नकली उर्वरक बनाने का काम पिछले कुछ सालों से योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। फिलहाल छापे की कार्रवाई के बाद अधिकांश फैक्टरियों के संचालक मौके से भाग छूटे हैं।

छापेमारी से खलबली, सैंपल लेने में जुटा विभाग

कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने जब नकली उर्वरक की फैक्ट्रियों पर छापेमारी की तो फैक्ट्री संचालक भाग छूटे। अब कृषि विभाग फैक्ट्री संचालकों की जानकारी जुटाकर नोटिस देने और उनके जवाब मांगने की कार्रवाई कर रहा है। विभाग के इंस्पेक्टरों को उनके संबंधित क्षेत्र में संचालित उर्वरक फैक्ट्रियों से सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं।

फर्टिलाइजर से शॉर्ट टर्म उपज बढ़ी, जमीन की गुणवत्ता घटी

कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल ज्वाइंट डायरेक्टर केके मंगल का कहना है कि हरित क्रांति के दौरान कृषि में कैमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़ने से पैदावार भी 30 से 40 फीसदी तक बढ़ी। हालांकि इस दौरान गोबर की खाद, राख का उपयोग जमीन की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए बेहद जरूरी होता है। जबकि नकली उर्वरकों के लंबे समय तक उपयोग होने पर जमीन की पैदावार निश्चित रूप से प्रभावित होना तय है।

जमीन को बंजर कर रहे कैमिकल

नकली उर्वरकों में मिलाए मार्बल स्लरी में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट से खेत में मिट्टी के ऊपर की परत ठोस होने के कारण जमीन की पानी को सोंखने की क्षमता में गिरावट होती है। जिसका सीधा असर फसलों की उपज पर पड़ता है। मार्बल स्लरी पाउडर से फसलों को जरूरी मिनरल और पानी नहीं मिलने पर धीरे धीरे जमीन की पैदावार क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है।

खेती की जमीन का पीएच-7 जरूरी

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार खेती के लिए मिट्टी का पीएच-7 होना बेहद आवश्यक है। मिट्टी का पीएच- 7 से कम होने पर उसमें अम्लीयता बढ़ जाती है, और पीएच- 7 से अधिक होने पर क्षारीयता बढ़ जाती है। नकली उर्वरकों में मिलाए जा रहे मार्बल स्लरी पाउडर और जिप्सम से जमीन की क्षारीयता बढ़ती है। राख की मिलावट पीएच को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है।

नारी हर जिम्मेदारी निभाने में निपुण

अहिल्याबाई होलकर ने दिया था नेतृत्व का प्रमाण-वसुंधराराजे

जयपुर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नारी शक्ति के सामर्थ्य को रेखांकित करते हुए कहा है कि नारी हर जिम्मेदारी निभाने में निपुण होती है, चाहे वह घर-परिवार की %राशन% संभालने की जिम्मेदारी हो या देश-प्रदेश के %शासन% की। उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि अहिल्याबाई ने ही यह सिद्ध कर दिया था कि नारी शक्ति में नेतृत्व के संपूर्ण गुण विद्यमान हैं। राजे ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के ऐतिहासिक कार्यकाल में मोदी सरकार द्वारा %नारी शक्ति वंदन अधिनियम% को मंजूरी देना पूज्या अहिल्याबाई होलकर जैसी वीरांगनाओं को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने महिलाओं के दैनिक जीवन में किए जाने वाले अथक कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिलाएं उसी सड़क पर चलकर घर आती हैं, जिस पर चलकर पुरुष आते हैं, लेकिन वे पुरुषों की तरह यह नहीं कहतीं कि ओहो मैं थक गई।

राजे ने आगे कहा कि महिलाएं घर और बाहर का पूरा काम करती हैं। वे खाना बनाती हैं, खिलाती हैं, बर्तन साफ करती हैं, लेकिन फिर भी पुरुषों की तरह जूते फेंक कर यह नहीं कहतीं कि मैं थक गई। यह टिप्पणी महिलाओं के अदम्य साहस और समर्पण को उजागर करती है, जो बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर को धर्म की रक्षक ऐसी शासक बताया, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में, बद्रीनाथ से लेकर रामेश्वरम तक और द्वारिका से लेकर पुरी तक, आक्रमणकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। इनमें काशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। राजे ने अहिल्याबाई के इस योगदान को उनके धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत के प्रति समर्पण का प्रमाण बताया।

सरकारी घोषणाओं के झरनों में सूखते भारत की पुकार!

नीति आयोग की 'जल प्रबंधन सूचकांक' 2018 की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि 2030 तक देश के 21 शहरों का भूजल पूरी तरह समाप्त हो सकता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी 15 करोड़ से ज्यादा लोग स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं। विगत वर्षों में लातूर को ट्रेन से पानी भेजना पड़ा, बुंदेलखंड में महिलाएं निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करती हैं, और झारखंड के गाँवों में लोग पेड़ों से रिसती बूंदों को जमा करके पीते हैं। ये घटनाएं 21वीं सदी की नहीं लगतीं, फिर भी ये हमारे आज की सच्चाई हैं। विश्वगुरु बनाने को लालायित देश की हक़ीक़त है, लेकिन रहनुमाओं को सिर्फ़ अपनी फ़िक्र है।

(लेखिका - सोनम लववंशी)

पानी के लिए तरसती आंखें, सूखते कंठ, और एक झूठ जो हर चुनावी मंच पर झाग की तरह फूटता है—'हर घर नल से जल'। महाराष्ट्र के नासिक जिले का पेठ तालुका और उसका एक छोटा-सा गांव बोरीचिवारी, उस झूठ का ऐसा आईना है जिसमें सत्ता का चेहरा अब भी चमकता नहीं, बल्कि धुंधलाता हुआ नज़र आता है। यहाँ की महिलाएं आज भी जान हथेली पर रखकर कुएं में उतरती हैं, अपने और अपने परिवार के लिए कुछ बूंदें पानी की तलाश में। विकास के दावों की छाती पर चढ़कर जब लोकतंत्र की ये बेटियाँ रस्सियों के सहारे नीचे उतरती हैं, तब यह दृश्य 'अमृतकाल' नहीं, अपवित्र त्रासदी की गाथा गढ़ता है। वैसे ये तस्वीर सिर्फ़ नासिक के एक गांव की नहीं, सूखते कंठ की दर्द भरी दास्तां राष्ट्रव्यापी समस्या बन चुकी है। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर झारखंड के पलामू तक, जल संकट की त्रासदी एक ऐसी सच्चाई है, जो सरकार के 'हर घर जल' जैसे तमाम वादों और अभियानों की पोल खोलती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराने का दावा किया गया, लेकिन कैग और नीति आयोग की रिपोर्टें बताती हैं कि यह योजना आंकड़ों के मायाजाल से आगे नहीं बढ़ पाई।

नीति आयोग की 'जल प्रबंधन सूचकांक' 2018 की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि 2030 तक देश के 21 शहरों का भूजल पूरी तरह समाप्त हो सकता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी 15 करोड़ से ज्यादा लोग स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं। विगत वर्षों में लातूर को ट्रेन से पानी भेजना पड़ा, बुंदेलखंड में महिलाएं निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करती हैं, और झारखंड के गाँवों में लोग पेड़ों से रिसती बूंदों को जमा करके पीते हैं। ये घटनाएं 21वीं सदी की नहीं लगतीं, फिर भी ये हमारे आज की सच्चाई हैं। विश्वगुरु बनाने को लालायित देश की हक़ीक़त है, लेकिन रहनुमाओं को सिर्फ़ अपनी फ़िक्र है। तभी तो बोतलबंद पानी पीने वाले नेतागण 'नमामि गंगे', 'अटल भूजल योजना' और 'जल क्रांति अभियान' जैसे कार्यक्रम को शुरू कर ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के अनुसार, ग्रामीण महिलाओं को प्रतिदिन 2-3 घंटे पानी लाने में गंवाने पड़ते हैं, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होता हैं। जबकि यूनेस्को की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में जल संकट सामाजिक असमानता और जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर एक गहरी मानवीय आपदा का रूप ले चुका है, और यह अब चेतावनी नहीं, बल्कि वास्तविकता है।

इतना ही नहीं स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति जल की अनुपलब्धता के कारण भी प्रभावित होती है। यूनेस्को की ही एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, जल संकट वाले क्षेत्रों में लड़कियों की ड्रॉप-आउट दर लगभग 23 प्रतिशत से अधिक होती है। दूसरी तरफ हमारी रहनुमाई व्यवस्था है, जो 2024 आकर बीत जाने के बाद भी 'हर घर नल' वाला सपना भूल गई है। पीएम मोदी ने लालकिले से घोषणा की थी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश के हर ग्रामीण घर को नल से शुद्ध पानी मिलेगा। सरकारी पोर्टल्स और पीआईबी की प्रेस रिलीज़ों में सफलता की झिलमिलाती कहानियाँ दर्ज हैं, करोड़ों कनेक्शन दिए जा चुके हैं, ग्राफ़ ऊपर की ओर जा रहे हैं और काग़ज़ों में भारत प्यासा नहीं है। लेकिन बोरीचिवारी में ज़मीन पर उतरते ही ये आँकड़े गले में अटक जाते हैं। महिलाओं के हाथों में मटके हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं, शिकायतें भरी हैं। कुएं में उतरकर पानी निकालने की उनकी आदत आज़ादी के 75 साल बाद भी नहीं छूटी, क्योंकि 'नल' उनके घर की दीवारों पर सिर्फ़ एक मेटल का पाइप है जो सूखा और खामोश है। ऐसे में क्या यही है 'अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस' मनाने का औचित्य? क्या यही है यूनिसेफ और नीति आयोग की सिफारिशों पर खरे उतरने वाला भारत? यदि जल जीवन मिशन इतना सफल रहा है, तो फिर क्यों पेठ तालुका के बोरीचिवारी, भोर, त्र्यंबकेश्वर, अक्कलगांव जैसे गांवों की बच्चियां स्कूल के बजाय दिन भर पानी की लाइन में लगी रहती हैं? क्या उनके लिए शिक्षा का अधिकार अब भी सिर्फ किताबों में छपी इबारत है?

भारत के संविधान की धारा 21 'जीवन के अधिकार' की बात करती है, जिसमें स्वच्छ जल की उपलब्धता एक बुनियादी मानवीय अधिकार माना गया है। लेकिन इस अधिकार को पाने के लिए इन महिलाओं को कुएं की गहराई में उतरना पड़ता है, बिना सुरक्षा के महज एक रस्सी के सहारे। क्या इसी को 'सुशासन' कहते हैं? महाराष्ट्र में ही 2023-24 के बजट में जल संसाधन परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई थी। जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 3.6 लाख करोड़ का प्रावधान किया था। इन योजनाओं का लाभ किसे मिला? क्या ठेकेदारों को? क्या टेंडर लेने वाले निगमों को? या फिर अधिकारियों की ट्रैवल रिपोर्ट्स को, जिनमें प्रोजेक्ट्स ऑन ट्रैक लिखा होता है? सरकारें आती हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन प्यास नहीं बुझती। नासिक जैसे अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी जब ये स्थिति है, तो आदिवासी और घने जंगलों में बसे गांवों की दशा की कल्पना मात्र ही सिहरन पैदा कर देती है। पेठ का यह गांव न तो बाढ़ग्रस्त है, न भूकंप-प्रभावित, फिर भी यहाँ पीने का पानी नहीं। क्यों?

जल संकट कोई अचानक आई आपदा नहीं, यह तो लंबे समय से तैयार किया गया एक 'सामाजिक अपराध' है—संवेदनहीनता का परिणाम। ग्राउंड वाटर लेवल गिरता रहा, तालाब और जलाशयों पर मॉल खड़े होते रहे, जल संरचनाओं की मरम्मत कागजों तक सीमित रही, और जनता को आश्वासन के पानी से बहलाया जाता रहा। कभी सरकारी बाबू कहते हैं कि पाइपलाइन बिछाई जा रही है, तो कभी सरपंच कहते हैं कि बिजली नहीं है, पंप चालू नहीं हो सकता। लेकिन असली सवाल कोई नहीं उठाता कि आखिर इन योजनाओं की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? पेठ जैसी जगहों में आरटीआई के ज़रिए पूछे गए सवालों के जवाब अक्सर 'रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं' कहकर टाल दिए जाते हैं। जनसुनवाई की बैठकें नदारद हैं और जनता के हिस्से में सिर्फ एक 'सुनो और भूल जाओ' वाली व्यवस्था है।

यह तस्वीर केवल एक गांव की नहीं है, यह तस्वीर उस राष्ट्र की है जो अब भी अपनी 50 करोड़ ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पानी की न्यूनतम गारंटी नहीं दे सका है। दुनिया भर में 'जलवायु परिवर्तन' की बड़ी-बड़ी कांफ्रेंस में भारत भागीदारी करता है, लेकिन अपने गांवों में पानी की कमी से आत्महत्या करते किसानों की सूची तक नहीं बनाता। क्या हमने कभी सोचा है कि जब एक बच्ची हर दिन 3-4 घंटे पानी लाने में खर्च करती है, तो उसकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? जब एक माँ, जो प्रसव के बाद बमुश्किल ठीक हुई हो, कुएं में उतरती है, तो उसे जिंदगी की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है? और जब पानी की एक बाल्टी के लिए झगड़े होते हैं, तो समाज के ताने-बाने पर कैसा असर होता है? सरकारों के पास 'पानी पर राजनीति' का अद्भुत हुनर है। कभी इसे मुफ्त देने का वादा, कभी टैक्स घटाने का एलान, और कभी नदी जोड़ो योजना जैसे 'विकासशील स्वप्न'। लेकिन जब ज़मीनी हालात से इन्हें टकराया जाता है, तो हकीकत वही रहती है सूखे नल, टूटे बर्तन और कुएं में उतरती ज़िंदगियाँ।

क्या इन महिलाओं ने भारत माता की जय नहीं बोला? क्या इन्होंने भी वोट नहीं दिया था? क्या इनके आँसू भी राष्ट्रगीत के सुरों से कमज़ोर हैं? अगर नहीं, तो क्यों इनकी प्यास पर सिर्फ भाषण मिलता है, योजना नहीं? क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन है और जनता सिर्फ एक आँकड़ा? आज अगर बोरीचिवारी की कोई महिला संविधान की धारा 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दे कि उसे पीने के पानी की गारंटी दी जाए, तो क्या हम उसे विजयी कहेंगे या 'सरकारी तंत्र को बदनाम करने वाली'? दुख इस बात का है कि हम तकनीक की बात करते हैं, चंद्रयान की उपलब्धियों पर तालियाँ बजाते हैं, लेकिन धरती पर मौजूद कुएं के पानी तक पहुँचने के लिए हमारे पास कोई समाधान नहीं है। हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन बोरीचिवारी के लिए एक सिंपल पंप सेट भी नहीं लगा पाए और जब अगली बार प्रधानमंत्री कैमरे के सामने कहेंगे कि 'जल जीवन मिशन एक सफलता है', तो क्या बोरीचिवारी की कोई माँ अपना मटका दिखाकर पूछ सकेगी—'मोदी जी, इसमें क्या भरूं?' ऐसे में ये शब्द सिर्फ सरकार की विफलता पर कटाक्ष नहीं, बल्कि लोकतंत्र के असल मतलब की पुनर्परिभाषा है। पानी किसी का अहसान नहीं, यह हक़ है और जब हक़ नहीं मिलता, तो नागरिकता की गरिमा भी खो जाती है। बोरीचिवारी की महिलाएं नायक नहीं बनना चाहतीं, वे बस इंसान बनकर जीना चाहती हैं। वे पुरस्कार नहीं चाहतीं, उन्हें बस पानी चाहिए। इतना पानी, जितना किसी भी 'विश्वगुरु' देश के नागरिक को बिना जान गंवाए मिल सके, परंतु जब पानी भी एक 'विकास कथा' में बदल जाए, तो समझिए कि लोकतंत्र की आत्मा सूखने लगी है। शायद अब हमें कुएं में सिर्फ पानी नहीं, अपना जमीर भी तलाशना होगा।

संपादकीय

महंगी पड़ेगी सुस्ती

निस्संदेह, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी सुरक्षा उत्पादों की आपूर्ति में किसी भी लेट-लतीफी को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। खासकर ऐसे वक्त में जब देश की दो तरफ की सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियां बरकरार हैं। इसी आलोक में एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह की चिंताओं से सहमत हुआ जा सकता है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मेरे ख्याल से एक भी परियोजना तय सीमा पर पूरी नहीं होती है। निस्संदेह, यह कथन देश की स्वदेशी उत्पादों की रक्षा तैयारियों में विलंब की प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। देश के नेताओं का स्वदेशी सुरक्षा उत्पादों की जरूरत पर बल देना निस्संदेह, सराहनीय कदम है, लेकिन सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर उनकी समय पर आपूर्ति भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। खासकर तेजस लड़ाकू विमान व आकाश मिसाइल प्रणाली, के बावजूद लगातार होने वाली देरी परिचालन तत्परता को बाधित करती है। निस्संदेह, लेट-लतीफी की यह प्रवृत्ति आधुनिकीकरण को पटरी से भी उतार सकती है। दरअसल, यह देरी, जो अकसर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के चरण में ही स्वीकार कर ली जाती है, कालांतर प्रणालीगत जड़ता और अति-वायदे की संस्कृति को ही उजागर करती है। हमारे पड़ोसी देशों में तेजी से होते सैन्य आधुनिकीकरण और युद्ध तैयारियों में गहन तकनीक के इस्तेमाल होने के चलते, हमें इस सुस्ती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। निर्विवाद रूप से यह महज बजट या नौकरशाही की लालफीताशाही का मामला भर नहीं है। वास्तव में यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील विषय है। निस्संदेह, सरकार की ओर से घरेलू रक्षा उत्पादकता को बढ़ावा देने की पहल एक स्वागत योग्य कदम है। विगत के संकटकाल के दौरान देखने में आया है कि युद्ध व चुनौतिपूर्ण स्थितियों में हम विदेशों में अपनी जरूरत का सामान तलाशते रहे हैं। कई देशों ने मुश्किल वक्त में सामान की आपूर्ति में ना-नुकुर भी की है। कारगिल युद्ध के समय भी कुछ ऐसे अनुभव देखने में आए थे। राजग सरकार का घरेलू रक्षा उत्पादन की तरफ बढ़ाया गया कदम निस्संदेह सराहनीय है। यह उत्साहजनक है कि हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन कुल रक्षा जरूरतों का 65 प्रतिशत हो गया है, रक्षा निर्यात 24,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। साथ ही सार्वजनिक-निजी उत्पादन का संतुलन धीरे-धीरे पक्ष में जा रहा है। वहीं आईडीईएक्स जैसी योजनाएं नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि अब निजी क्षेत्र कुल रक्षा उत्पादन में 21 फीसदी का योगदान दे रहा है। लेकिन जब जरूरी रक्षा उत्पादों की आपूर्ति समय पर नहीं हो पाती, तो यह हमारी रणनीतिक स्वायत्तता के लिये असहज स्थिति पैदा कर देती है। दरअसल, यह स्थिति इस घरेलु उद्योग की संरचनात्मक विसंगतियों को दूर करने की जरूरत बताती है। इस दिशा में ध्यान देने की महती जरूरत है कि कच्चे माल की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही शोध व अनुसंधान तथा विकास के लिये पर्याप्त आर्थिक संसाधन समय रहते उपलब्ध कराए जाएं। यह दृष्टव्य है कि देश के 6.81 लाख करोड़ रुपये के रक्षा बजट में मात्र 1.8 लाख करोड़ रुपये की राशि आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित की गई है। उसमें शोध-अनुसंधान व विकास के लिये निर्धारित राशि आधुनिकीकरण के बजट में 3.94 फीसदी ही है। निश्चित रूप से जब तक इस वित्तीय संसाधनों के संतुलन को दुरुस्त नहीं किया जाता, तब तक हम समय की चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। निस्संदेह, देश के रक्षा क्षेत्र के तीन सार्वजनिक उपक्रमों यानी डीपीएसयू को 'मिनी रत्न' घोषित करना स्वागत योग्य कदम है।

भारत के लिए युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प है

(लेखक- - डॉ. राघवेन्द्र शर्मा)

भारतीय सनातन सभ्यता में ऐसे कई प्रसंग एक जैसे दर्ज हैं, जिन्हें देखकर और पढ़कर ऐसा प्रतीत होता रहा है मानो इतिहास स्वयं को दोहरा रहा हो। अनेक कालखंडों में, दशकों में, सदियों में और युगों में, हमने कई घटनाएं ऐसी पढ़ी हैं, जिनके अध्ययन उपरांत ऐसा लगता है जैसे आज जो हमारे रूबरू है उसे पहले भी कहीं और पहले भी देखा जा चुका है। उदाहरण के लिए हम भारत और पाकिस्तान के बीच स्थाई रूप से व्याप्त बने हुए तनाव को ले सकते हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है और भारत की ओर से जिस प्रकार से संयम, धैर्य का प्रदर्शन किया जा रहा है, यह हमें द्वापर युगीन कौरवों की अति और भगवान कृष्ण की सहृदयता का स्मरण कराता हैं। जब कौरवों के षडयंत्रों को पूरी तरह विफल करते हुए पांडव अपना अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रयासरत थे। तब उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में भगवान कृष्ण ने यह निर्णय लिया कि हमें अंत तक युद्ध के अलावा उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। ऐसा ही हुआ, भगवान कृष्ण ने शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर गमन किया और वहां उपस्थित दुर्योधन एवं धृतराष्ट्र सहित समस्त कुरुवंशियों को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का सहज समाधान नहीं हो सकता। इससे राज सत्ता पर अधिपत्य जमाए रखने की आकांक्षा पाले बैठे लोगों की तुष्टि भले ही होती हो, लेकिन अनिष्ट प्रजा का ही होता है। दोनों ही पक्ष की सेनाओं के हजारों लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनसे अधिक लोग सदा के लिए अपंग हो जाते हैं। फल स्वरुप मानव समाज को युगों युगों तक उस अपराध का असहनीय दंड भुगतना होता है, दरअसल जो उन्होंने किया ही नहीं होता। अतः टकराव का रास्ता छोड़ते हुए कुरु वंश को पांडवों का सम्मान बनाए रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने राजसभा में मौजूद प्रजा के गणमान्य प्रतिनिधियों और कुरु वंश के सामर्थ्यवान पदाधिकारियों को भी यह सीख दी कि वे दुर्योधन और धृतराष्ट्र की अपवित्र महत्वाकांक्षाओं को समझें और उन्हें पाप पूर्ण कृत्य करने से रोकें। ताकि युद्ध के रूप में आसन्न अनिष्ट एवं अनर्थ को रोका जा सके। सभी सामर्थ्यवान प्रबुद्ध जन चुपचाप बने रहे। वहीं काल के वशीभूत, अपने अनर्थ से अपरिचित दुर्योधन ने जब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और भगवान कृष्ण को ग्वाला, गायों को चराने वाला, आदि शब्दों से असम्मानित करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे डाला, तब यह तय हो गया कि अब कुरुवंशियों को काल के गाल में समाने से कोई नहीं रोक सकता। समूचा ब्रह्मांड जानता है कि केवल और केवल दुर्योधन एवं धृतराष्ट्र की हठ धर्मिता के चलते महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें लाखों लोग अकारण ही काल के गाल में समा गए। अंततः जीत सत्य स्वरूप श्री कृष्ण के सानिध्य में सज्ज पांडवों की ही हुई। वर्तमान परिवेश में देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति कुरु वंश और पांडवों जैसी ही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार-बार पाकिस्तान और वहां के हुक्मरानों को चेतावनी दे रहे हैं कि अंततः युद्ध विनाश का कारण होता है। जबकि वहां के हुक्मरान और सेना प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री के वक्तव्यों की ठीक उसी प्रकार अनदेखी कर रहे हैं, जैसे हस्तिनापुर की राजसभा में दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के प्रति असम्मानजनक व्यवहार का प्रदर्शन किया था। श्री मोदी जानते हैं कि पाकिस्तानी राजनेता और वहां की सेना भारत विरोधी एजेंडे को ही लंबे समय तक सत्ता पर काबिज बने रहने का जरिया मान कर बैठे हुए हैं। यही कारण है कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का भला चाहते हुए उसे भी आगाह किया है कि वह अपना भला बुरा समझे और दुनिया भर में आतंकवाद को निर्यात करने वाले वहां के नेताओं, हुक्मरानों तथा सेना की नापाक हरकतों को पहचानें, समय रहते उन्हें वास्तविकता का एहसास कराते हुए उन्हें भारत में आतंकवाद निर्यात करने के गलत रास्ते पर जाने से रोकें । यदि पाकिस्तानी अवाम के ईमानदार प्रयास हुए तो संभव है वह आने वाले समय में भारतीय सदाव्यता के चलते भुखमरी, कंगाली और निकट भविष्य में सन्निद्ध गृह युद्ध जैसी विभीषिका से स्वयं को बचा सकेगा। अब निर्णय पाकिस्तान को करना है कि उसे अपनी अवाम का पेट भरने के लिए रोटी की उपलब्धता उचित लगती है या फिर भारतीय सेना की गोलियों से मरना ज्यादा अच्छा लगता है। यहां कुछ-कुछ प्रसंग सीख के रूप में हम रामायण युगीन घटनाओं से भी ग्रहण कर सकते हैं। उस कालखंड में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उस स्थिति में भी लंका वासियों का भला करने का और उन्हें अनिष्ट से बचाए रखने का हर संभव प्रयास किया था, जबकि वहां का राजा रावण उनकी धर्मपत्नी सीता जी का अपहरण करने का पाप कर चुका था। भगवान कृष्ण के सानिध्य में सज्ज पांडव और प्रभु श्री राम की कृपा में तैनात वानर दल किसी भी दृष्टि से पाप पूर्ण कृत्यों में संलग्न शत्रु पक्ष का अनिष्ट करने में कमजोर नहीं थे। संकल्प मात्र से ही दुष्टों को नाश करने का सामर्थ्य उन्हें सहज ही प्राप्त था। लेकिन प्रभु श्री राम ने भी पहले हनुमान जी को लंका भेजा, जिन्होंने लंका जलाने से पहले रावण को बार-बार समझाया कि वह युद्ध को हर हाल में टालने का हर संभव प्रयास करे। इसी में राक्षस जाति की भलाई है। जब समुद्र पर सेतु बन गया। युद्ध को आतुर वानर सेना लंका के समक्ष हुंकार भरने लगी। तब प्रभु श्री राम ने एक बार फिर लंका को विनाश से बचाने का रास्ता खोजा और अंगद को शांतिदूत के रूप में प्रेषित किया। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, रावण के सिर पर भी काल मंडरा रहा था। सो उसे सामने खड़ा सत्य भी समझ नहीं आ रहा था, या फिर यू कहा जाए कि वह समझना ही नहीं चाहता था। बात त्रेता युग की हो या फिर द्वापर की, पाप पूर्ण कृत्यों में संलग्न पक्ष ने सत्य के मार्ग पर अडिग, धर्म परायण, सामर्थ्यवान, सज्जनों की सहृदयता को कमजोरी ही समझा और स्वतः ही मृत्यु के भोज्य बन बैठे। हाल ही में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रवास पर गए तब उन्होंने भुज की पवित्र भूमि से भारत और पड़ोसी देश को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के ऐसे प्रयास हैं, जिनके माध्यम से हमने आतंकवादियों का तो नाश किया, उनके प्रशिक्षण कैंपों को भी ध्वस्त किया।

(चिंतन-मनन)

संत की सीख

एक धनी सेठ ने एक संत के पास आकर उनसे प्रार्थना की, महाराज, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करता हूं पर मेरा मन एकाग्र ही नहीं हो पाता है। आप मुझे मन को एकाग्र करने का कोई मंत्र बताएं। सेठ की बात सुनकर संत बोले, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें एकाग्रता का मंत्र प्रदान करूंगा। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। उसने इसे अपना सौभाग्य समझा कि इतने बड़े संत उसके घर पधारेंगे। उसने अपनी हवेली की सफाई करवाई और संत के लिए स्वादिष्ट पकवान तैयार करवाए। नियत समय पर संत उसकी हवेली पर पधारे। सेठ ने उनका खूब स्वागत-सत्कार किया। सेठ की पत्नी ने मेवों व शुद्ध घी से स्वादिष्ट हलवा तैयार किया था। चांदी के बर्तन में हलवा सजाकर संत को दिया गया तो संत ने फौरन अपना कमंडल आगे कर दिया और बोले, यह हलवा इस कमंडल में डाल दो। सेठ ने देखा कि कमंडल में पहले ही कूड़ा-करकट भरा हुआ है। वह दुविधा में पड़ गया। उसने संकोच के साथ कहा, महाराज, यह हलवा मैं इसमें कैसे डाल सकता हूं। कमंडल में तो यह सब भरा हुआ है। इसमें हलवा डालने पर भला वह खाने योग्य कहां रह जाएगा, वह भी इस कूड़े-करकट के साथ मिलकर दूषित हो जाएगा। यह सुनकर संत मुस्कराते हुए बोले, वत्स, तुम ठीक कहते हो। जिस तरह कमंडल में कूड़ा करकट भरा है उसी तरह तुम्हारे दिमाग में भी बहुत सी ऐसी चीजें भरी हैं जो आत्मज्ञान के मार्ग में बाधक हैं। सबसे पहले पात्रता विकसित करो तभी तो आत्मज्ञान के योग्य बन पाओगे। यदि मन-मस्तिष्क में विकार तथा कुसंस्कार भरे रहेंगे तो एकाग्रता कहां से आएगी। एकाग्रता भी तभी आती है जब व्यक्ति शुद्धता से कार्य करने का संकल्प करता है। संत की बातें सुनकर सेठ ने उसी समय संकल्प लिया कि वह बेमतलब की बातों को मन-मस्तिष्क से निकाल बाहर करेगा।

विचार मंथन

चीन के नेतृत्व में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन

(लेखक- सनत जैन)

- चीन की यूनाइटेड नेशन को चुनौती

चीन वैश्विक राजनीति में बड़ी ताकत के साथ तेजी कदम बढ़ा रहा है। चीन अब सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं, वरन वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण है, चीन के नेतृत्व इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन की स्थापना की गई है। चीन के नेतृत्व में हांगकांग में शुरू यह नया बहुपक्षीय मंच है। इस संगठन का उद्देश्य वैश्विक अथवा दो देशों के बीच के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना इसका मुख्य उद्देश्य है, इसके राजनीतिक आर्थिक निहितार्थ को लेकर गंभीर और दूरगामी परिणाम होना तय है। संयुक्त राष्ट्र जैसे स्थापित वैश्विक संस्थानों की निष्क्रियता, पक्षपात और राजनीतिक दवाब को देखते हुए चीन ने एक समानांतर वैश्विक संस्था खड़ा करने की कोशिश की है। यह संस्था ऐसे समय में सामने आई है। जब रुस एवं यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध, इजरायल-गाज़ा का संकट, ताइवान तनाव और दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सवालों के घेरे में है।

सारी दुनिया आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़ी है। विश्व के अधिकांश देश कर्ज एवं महंगाई से जूझ रहे है। सारी दुनिया तकनीकि के विकास को लेकर जिस तेजी से बदल रही है। ऐसे समय पर चीन का वैश्विक स्तर पर ताकतवर होना भारत के लिये बड़ी चुनौती है। अमेरिका और रूस इस समय सबसे कमजोर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान क्रियाकलाप से दुनिया के देशों में उसकी विश्वसनीयता और कार्य प्रणाली को लेकर अविश्वास पैदा हुआ है। ऐसे समय में चीन ने हांगकांग को मध्यस्थता का केंद्र बिन्दु बनाकर वैश्विक नेतृत्व की दुनिया के देशों के बीच नई दावेदारी पेश कर दी है। इस संगठन में 85 देशों की भागीदारी है। 33 देशों की फाउंडर सदस्यता है। वर्तमान संदर्भ में चीन की कूटनीतिक राजनीतिक एवं आर्थिक सफलता को दर्शाती है। इस संगठन की खास बात यह है, इनमें से कई देश वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ के) देश हैं। दुनिया भर के विकासशील या पिछड़े राष्ट्र पश्चिमी प्रभाव से मुक्त होकर नये साझेदारों की तलाश मे हैं। नया संगठन इस तलाश की पुष्टि कर रहा है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे लोकतांत्रिक देशों को इसमें शामिल नहीं है। विकसित राष्ट्र खुद शामिल नहीं हुए हैं? विकशित एवं विकासशील राष्ट्रों की अनुपस्थिति से स्पष्ट है, अब दुनिया दो धड़ों में बंटने जा रही है। दुनिया में चीन का प्रभाव बड़ी तेजी के साथ बढा है, यह भी इससे प्रमाणित होता है। चीन अब बड़ी आर्थिक एवं सामरिक शक्ति के रूप में वैश्विक स्तर पर उभर रहा है। हांगकांग में इस संस्था का मुख्यालय बनना भी प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। यह वही हांगकांग है, जो कभी लोकतंत्र की प्रयोगशाला था। अब चीन की राजनीतिक पकड़ और प्रभाव में है। हॉन्गकांग में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखना चीन का साफ संदेश है। नई व्यवस्था लोकतंत्र के साथ-साथ वित्तीय एवं सामरिक नियंत्रण की रणनीति पर आधारित होगी। भारत के लिए यह एक बडी चेतावनी है। भारत इस तरह के संगठनो से दूरी बनाएगा, तो भारत वैश्विक विचार विमर्श, करोबार से बाहर होता चला जाएगा। चीन ने अंतरराष्ट्रीय संस्था तैयार कर इसमें 85 देशों का समर्थन हासिल करके सारी दुनिया के देशों और महा शक्तियों को चुनौती दी है। संयुक्त राष्ट्र को भी चीन ने एक तरह से चुनौती दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ यदि कमजोर होता है ऐसी स्थिति में भारत के लिए आने वाले समय में मुश्किलें और भी बढ़ना तय है। अब भारत को तय करना है, क्या वह पुरानी व्यवस्था के साथ जुड़ा रहकर वैश्विक संस्थाओं और स्वयं की रक्षा करेगा, या नई वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए अपने आप को बदलेगा। भागीदारी, वैश्विक स्तर पर और पड़ोसी देशों के साथ भारत किस तरह से आगे बढ़ेगा यह भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चीन भारत का पड़ोसी है। भारत की बहुत बड़ी सीमा चीन के साथ लगी हुई है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार की सीमाएं भारत से जुड़ी हुई है। उपरोक्त सभी देश चीन के प्रभाव में है उपरोक्त देशों के साथ चीन के आर्थिक और सामरिक संबंध पिछले एक दशक में बड़े मजबूत हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारत पर सबसे ज्यादा दबाव में होगा। चीन की आर्थिक और सामरिक शक्ति भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इसलिए भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर जो बदलाव हो रहे हैं, उसको देखते हुए भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने हितों की रक्षा करने के लिए ज्यादा सजग रहना होगा।

पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को केंद्रित कर कहा- नारी शक्ति को चुनौती देना आतंकियों के लिए बन गया काल

देवी अहिल्याबाई होल्कर जयंती पर इंदौर मेट्रो और सतना-दतिया एयरपोर्ट किया लोकार्पित

भोपाल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के पावन अवसर पर इंदौर मेट्रो और सतना-दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए मातृशक्ति को नमन किया और देवी अहिल्याबाई के योगदान को युगों तक याद रखने वाला बताया।

राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी और यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। हमारी सेनाओं ने सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के अड्डों को नष्ट कर दिया।

ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन बन गया है। यहां पर पीएम मोदी ने देवी अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत की सशक्त संरक्षक बताया।

उन्होंने कहा, कि जब देश में संस्कृति और मंदिरों पर हमले हो रहे थे, तब अहिल्याबाई ने उन्हें संजोने का संकल्प लिया और सैकड़ों मंदिरों और तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण कराया। पीएम मोदी ने कहा कि देवी अहिल्याबाई ने महेश्वरी साड़ी उद्योग की नींव रखकर हजारों बुनकर परिवारों को रोज़गार दिया और गुजरात से हुनरमंद कारीगरों को लाकर इस कला को नया जीवन दिया। उन्होंने कहा, कि बहुत कम लोगों को पता है कि देवी अहिल्या हुनर की बड़ी पारखी थीं।

महिला सशक्तिकरण की प्रेरणास्रोत

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अहिल्याबाई ने उस युग में नारी सुरक्षा टोलियों का गठन किया था, जब समाज में स्त्री अधिकारों की चर्चा भी दुर्लभ थी। उन्होंने बेटियों की शादी की उम्र, शिक्षा और अधिकारों को लेकर ठोस पहल की, जो आज भी समाज के लिए प्रेरणा है।

कृषि और जल प्रबंधन में अद्वितीय योगदान

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देवी अहिल्या ने कपास और मसालों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, कि आज हम क्रॉप डायवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन अहिल्याबाई ने यह सोच तीन सौ साल पहले अपनाई थी। उन्होंने नहरों और तालाबों का निर्माण कर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

शासन का लोककल्याणकारी मॉडल

पीएम मोदी ने कहा कि अहिल्याबाई ने शासन का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें गरीबों, वंचितों, आदिवासियों और श्रमिक वर्ग को प्राथमिकता दी गई। उनका गवर्नेंस मॉडल आज भी हमारे लिए आदर्श है। उन्होंने प्रभु सेवा और जन सेवा को कभी अलग नहीं माना।

विकास परियोजनाओं का शुभारंभ

इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने इंदौर मेट्रो और सतना-दतिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाओं को बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। इस पवित्र दिवस पर विकास के इन सभी कार्यों के लिए मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं।

संक्षिप्त समाचार

कोसी एक्सप्रेस के एसी कोच से अचानक उठने लगा धुआं, यात्रियों में मची भगदड़

संसू।

बिहार के पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत सहरसा मानसी रेलखंड के सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन से कुछ ही दूरी पर पुरैनी-गोरगामा के बीच शनिवार सुबह पूर्णिया कोर्ट से पटना जा रही कोसी एक्सप्रेस अचानक गोरगामा और पुरानी के बीच में रुकी और यात्री इधर-उधर भागने लगे। घटना के संबंध में सिमरी बख्तियारपुर से पटना जा रहे एक यात्री ने बताया कि कोसी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब बीस मिनट की देरी से सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पहुंची। यहां से ट्रेन आगे की ओर रवाना हुई। जैसे ही कोसी एक्सप्रेस ट्रेन पुरैनी व गोरगामा के समय पहुंची अचानक ट्रेन के एसी कोच बी-1 में धुआं भर गया। ट्रेन में धुआं भरते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, यात्रियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए चेन खींचकर ट्रेन को रोका। जैसे ही ट्रेन रुकी ट्रेन से उतरकर यात्री इधर-उधर भागने लगे। घटना की सूचना पर ट्रेन में मौजूद रेल कर्मियों ने तुरंत स्थिति को सामान्य किया। इस दौरान ट्रेन करीब आधे घंटे तक रुकी रही। स्थिति सामान्य होने के बाद यात्रियों को ऐसी कोच से दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

पीएम की रैली में बंगाल सरकार के खिलाफ चलाया 'दुर्भावनापूर्ण' अभियानः ममता

कोलकाता।

पीएम नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर हिंसा, भ्रष्टाचार और अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि राजनीति से प्रेरित होकर उनकी सरकार के खिलाफ एक ''दुर्भावनापूर्ण और झूठा अभियान'' चलाया गया। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में गुरुवार को एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मुर्शिदाबाद दंगों और शिक्षक भर्ती घोटाले का हवाला दिया और दावा किया कि राज्य के लोग ''निर्मम सरकार'' को हटाने के लिए बेताब हैं। सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में राजनीति से प्रेरित होकर एक दुर्भावनापूर्ण और झूठा अभियान चलाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह एक ऐसा अभियान था, जिसके तहत अलीपुरद्वार जिले के लोगों के लिए हमारी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को कमतर बताने और मिटाने का प्रयास किया गया।

दोपहर 3.15 पर दो सरकारी भवन उड़ जाएंगे, सभी को वहां से निकाल लो

सुबह करीब 6 बजे अधिकारियों को मिला मेल, जांच के बाद धमकी झूठी निकली

नई दिल्ली।

दिल्ली में दो प्रमुख सरकारी इमारतों, उद्योग भवन और निर्माण भवन को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिये मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरु किया है। जांच के बाद यह धमकी झूठी निकली। दोनों केंद्रीय सरकारी परिसरों के वरिष्ठ अधिकारियों को सुबह 6:49 बजे ई-मेल के जरिए धमकी दी गई थी कि परिसर में आईईडी लगाए गए हैं और चेतावनी दी कि दोपहर 3:15 बजे तक सभी को वहां से निकाल लें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों इमारतों में स्थित मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों को सुबह 6:49 बजे एक जैसे ई-मेल भेजकर आत्मघाती आईईडी की धमकी दी गई। उद्योग भवन में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ-साथ भारी उद्योग मंत्रालय का कार्यालय भी है, जबकि निर्माण भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों के कार्यालय हैं। रिपोर्ट में सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह फर्जी ई-मेल विदेश से भेजे जाने का शक है और केंद्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। शनिवार सुबह दोनों भवनों में तलाशी शुरु की गई। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि कोई भी आपत्तिजनक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और दोपहर बाद यह धमकी झूठी साबित हुई। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है कि यह मेल किसने भेजा।

पाकिस्तान से सटे कई राज्यों मे चलेगा ऑपरेशन शील्ड, सभी को तैयार रहने की जरुरत

नई दिल्ली।

जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों के साथ ही पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ के सीमावर्ती जिलों में यह मॉक ड्रिल की जाएगी। पहले यह मॉक ड्रिल 29 मई को होनी थी लेकिन फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। प्रशासन ने बताया कि अब तैयारियां पूरी हो गई हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच सीमावर्ती 6 राज्यों में शनिवार को ऑपरेशन शील्ड के तहत सुरक्षा की मॉक ड्रिल की जाएगी। इस ऑपरेशन शील्ड का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को युद्ध की स्थिति के लिए तैयार करना है। इसके हत यह बताया जाएगा कि युद्ध के समय खुद को और अपने आसपास के लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। ऑपरेशन शील्ड के दौरान सायरन बजेंगे और कुछ देर के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा। इन्वर्टर, सोलर लाइट और मोबाइल की टॉर्च के अलावा वाहनों की लाइट जलाने पर भी पाबंदी होगी। मॉक ड्रिल के दौरान लोगों से कहा गया है कि वे अपनी खिड़कियों के पर्दे भी बंद कर दें ताकि किसी तरह की रोशनी बाहर ना निकले। प्रशासन ने इसकी जानकारी लोगों तक पहले ही पहुंचा दी है ताकि लोगों में किसी तरह का पैनिक ना हो। यह मॉकड्रिल इसलिए कराई जा रही है ताकि एयरक्राफ्ट, ड्रोन या फिर मिसाइल हमले के वक्त लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। इस ड्रिल के तहत बेहद शांत तरीके से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बुलया जाएगा। इसके बाद इवैकुएशन ड्रिलल होगी। आपस में बातचीत के तरीकों को लेकर भी मॉक ड्रिल की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद सीमावर्ती जिलों में मॉकड्रिल की गई थी। पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए राज्यों को रिस्क ज्यादा होता है। यहां हवाई हमले और ड्रोन से हमले होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। ऐसे में सरकार का फोकस इन इलाकों में ज्यादा होता है। ब्लैकआउट से दुश्मन के लिए रिहाइशी इलाकों की पहचान कर हमला करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मॉक ड्रिल के दौरान भी ब्लैकआउट किया जाता है। बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमले शुरू कर दिए जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की बौखलाहट और खीझ को देखते हुए ही यह मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। यह ड्रिल 7 मई वाली ड्रिल की तरह ही होगी।

तेजी से पैर पसार रहा कोरोना, देशभर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 3207 हुई

केरल में सबसे ज्यादा 1147 मामले

नई दिल्ली।

देशभर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 3207 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1147 मामले हैं। महाराष्ट्र सक्रिय केस के मामले में दूसरे नंबर पर है। शुक्रवार को राज्य में 84 नए केस सामने आए, यहां अब 681 मरीज हैं। देश के 60 फीसदी सक्रिय केस इन्हीं दो राज्यों में हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 20 पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हैं। कर्नाटक के मैसूर में शुक्रवार को 63 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से यह तीसरी मौत है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने 31 मई को दिल्ली, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में भी एक-एक मौत की पुष्टि की। गुजरात के अहमदाबाद में शुक्रवार को एक दिन के नवजात की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

बच्चे को आईसीयू में रखा गया है। पिछले सप्ताह बच्चे की मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, हालांकि अब उनकी रिपोर्ट निगेटिव है। मेघालय में 7 महीने बाद कोविड के 2 मिले हैं। वहीं उत्तरपूर्व के राज्य मिजोरम में 2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में इस तरह का आखिरी मामला सामने आने के 7 महीने बाद कोविड के केस मिले। मिजोरम में कोविड-19 का आखिरी मामला अक्टूबर 2024 में सामने आया था, तब राज्य में 73 लोग वायरस से संक्रमित हुए थे।

उन्होंने बताया कि मरीजों का इलाज आइजोल के पास फल्कोन में जोरम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। महाराष्ट्र में 9 हजार से ज्यादा कोविड टेस्ट

महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि शुक्रवार को कोविड के 84 नए मामले सामने आए।

जबकि मुंबई में जनवरी 2025 से अब तक कुल 681 केस मिले हैं। जनवरी से अब तक राज्य में 9592 कोविड-19 टेस्ट किए गए।

वहीं, जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को कोविड-19 के दो मामले सामने आए थे। दोनों मरीज केरल के रहने वाले हैं और श्रीनगर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं।

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर लॉ स्टूडेंट गुरुग्राम से गिरफ्तार

गुरुग्राम।

ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुणे की एक लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पनोली द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा वीडियो एक विशेष धर्म को निशाना बनाकर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था।

हालांकि वीडियो बाद में हटा लिया गया, लेकिन तब तक वह वायरल हुआ व्यापक आक्रोश का कारण बना।वीडियो के खिलाफ कोलकाता के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर एफआईआर दायर की गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, +यह मामला एक महिला द्वारा साझा किए गए इंस्टाग्राम वीडियो से जुड़ा है, जिसमें एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बातें कही गई थीं। पुलिस का कहना है कि पनोली और उनके परिवार को कानूनी नोटिस देने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन वे घर पर नहीं मिले और जानबूझकर फरार हो गए।

एक ने नेत्रदान किया दो लोगों को मिली आंख की रोशनी

पटना।

अब वो अंधेरी दुनिया से लौट आए हैं। सबकुछ बेहतर दिख रहा है और नेत्र देने वाले को धन्यवाद दे रहे हैं। पटना एम्स में नेत्र बैंक बनने के 10 माह बाद किसी व्यक्ति ने नेत्रदान दिया। इसके बाद पहली बार कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया गया। इससे लोगों को रोशनी वापस लौटी। इस ट्रांसप्लांट को नेत्र विभाग के हेड डॉ अमित राज के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने पूरा किया। इस मौके पर डॉ। अमित ने बताया कि एम्स पटना में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीडित 100 से अधिक मरीज पंजीकृत हैं लेकिन डोनर नहीं मिलने के कारण सभी इंतजार कर रहे हैं। पटना एम्स में पहली बार कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दुल्हिन बजार के 55 वर्षीय पुरुष और संपतचक की 30 वर्षीया महिला की आंखों की रोशनी लौटाई गई। एक ट्रांसप्लांट में 45 मिनट से एक घंटे का समय लगता है। बता दें कि 55 वर्षीय व्यक्ति की आंखों का कॉर्निया 14 वर्ष की उम्र में चोट लगने की वजह से सफेद और धुंधला हो चुका था। एम्स पटना में नेत्र विशेषज्ञों की टीम ने पहले मोतियाबिंद की सर्जरी की और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी से नया कॉर्निया प्रत्यारोपित किया। अब इस मरीज को पहले की तरफ साफ-साफ दिखाई दे रहा है।दूसरी मरीज, 30 वर्षीया महिला पटना के संपतचक की रहने वाली हैं। कुछ समय पहले उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ था। यह इतनी तेजी से फैला कि देखते ही देखते इंफेक्शन एक आंख की कॉर्निया को पिघलाने लगा। धीरे-धीरे उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो गई। चिकित्सीय केराटोप्लास्टी के माध्यम से नया कार्निया प्रत्यारोपित किया गया और संक्रमण फैलने से रोका गया।

इन दोनों लोगों की रोशनी तभी लौट पाई जब एक व्यक्ति ने नेत्रदान किया। जमीनी हकीकत यह है कि लोग नेत्रदान के प्रति जागरूक नहीं हैं। इस वजह से कॉर्निया नहीं मिल पा रहा है। इसके इंतजार में पटना एम्स में 100 से अधिक मरीज पंजीकृत हैं, वे लंबे समय से कॉर्निया ट्रासप्लाट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, कॉर्निया डोनर की संख्या बिल्कुल सीमित है।

भागलपुर-दुमका रेलखंड में 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, जल्द होगा ट्रायल

भागलपुर।

भागलपुर-हावड़ा वंदे भारत, दुमका-पटना एक्सप्रेस, वनांचल एक्सप्रेस सहित कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का भागलपुर-दुमका रेलखंड में संचालन हो रहा है। इसके मद्देनजर भागलपुर से दुमका के बीच ट्रैक की स्पीड 110 किलोमीटर प्रतिघंटा से बढ़ाकर 120 से 130 किलोमीटर प्रतिघंटा की जानी है।इसको लेकर अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) लखनऊ भागलपुर-दुमका रेलखंड का स्पीड ट्रायल करने वाला था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते टाल दिया गया है।अब किसी और दिन ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया जाएगा। जल्द ही इसके लिए नई डेट तय की जाएगी। अब तक नई डेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

अधिकारियों के साथ वे विंडो ट्रेलिंग करते हुए बारापलासी, गोड्डा और बांका जाएंगे। जहां यात्री सुविधाओं सहित संरक्षा कार्यों को देखेंगे। डीआरएम शनिवार को सुबह 6.15 बजे भागलपुर से निरीक्षण ट्रेन से गोड्डा के लिए निकलेंगे। सुबह आठ बजे गोड्डा पहुंचने के बाद एक घंटे तक स्टेशन के विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद बारापलासी और बांका रेलखंड व स्टेशनों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे भागलपुर पहुंचेंगे और यहां निरीक्षण करेंगे। ट्रैक की स्पीड बढ़ने से ट्रेनों के संचालन में सुविधा होगी। ट्रैक की स्पीड बढ़ने से ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव किया जा सकता है। एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस बीच शनिवार को मालदा रेल प्रबंधक (डीआरएम) मनीष कुमार गुप्ता भागलपुर से हंसडीहा रेलखंड का निरीक्षण करने जाएंगे।

आतंकवाद के आकाओं को चुकानी होगी बड़ी कीमत, जयशंकर की पाक को चेतावनी

दीक्षांत समारोह में छात्रों को किया संबोधित

वडोदरा।

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वडोदरा से पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंक के आकाओं को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा नीति जीरो टॉलरेंस पर आधारित है और राष्ट्रहित में कोई भी निर्णय दबाव में नहीं, बल्कि मजबूती से लिए जाते हैं।

दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर वडोदरा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्रों के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने कहा कि हम कभी भी न्यूक्लियर के नाम पर ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेंगे। भारत के राष्ट्रीय हितों से जुड़े जो भी निर्णय लेने जरूरी हैं, वे लिए गए हैं और लिए जाते रहेंगे। जयशंकर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अब आतंकवाद के केंद्र अछूते नहीं रहेंगे। आतंकवाद को पालने-पोसने और उसे रणनीतिक साधन की तरह इस्तेमाल करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हालिया आतंकी हमले को लेकर देश में रोष व्याप्त है। इस आतंकी हमले को पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक नफरत फैलाने की साजिश करार देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयासों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और दिया गया है। उन्होंने 26/11 मुंबई हमले का हवाला देते हुए कहा कि पहले भी भारत को आतंक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़ी थी, लेकिन अब देश की सुरक्षा नीति कहीं अधिक मुखर और निर्णायक हो चुकी है। जयशंकर ने भारत की विदेश और सुरक्षा नीति की तीन प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करते हुए कहा, निर्णय लेने में दबाव नहीं सहा जाएगा, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होंगे और आतंकवाद पर पूर्ण प्रतिबंध और आक्रामक प्रतिरोध जारी रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की रणनीति अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सक्रिय प्रतिरोध और रोकथाम पर आधारित है।

यहां बताते चलें कि विदेश मंत्री जयशंकर का यह बयान शांग्री-ला डायलॉग में सीडीएस जनरल अनिल चौहान के कड़े रुख के बाद आया है, जहां भारत ने पाकिस्तान और चीन को लेकर अपनी नवीन रणनीति और आत्मनिर्भर सुरक्षा दृष्टिकोण को दोहराया। अब भारत का आतंकवाद और उसके आकाओं के लिए कड़ा संदेश है, कि भारत अब सहन नहीं करता, भारत अब उत्तर देता है।

मिजोरम में बारिश ने मचाई तबाही, 5 मकान व होटल ढही, कई मलबे में दबे

लॉन्गतलाई।

पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पहुंचने से पहले ही भारी बारिश जारी है। मिजोरम और असम में बारिश ने बुरा हाल कर रखा है। दक्षिणी मिजोरम के लॉन्गतलाई शहर में भारी बारिश से हुए भूस्खलन में पांच मकान और एक होटल ढहने से कई लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि शुक्रवार रात लॉन्गतलाई के बाजार वेंग और चांदमारी इलाकों के सीमावर्ती इलाके में भूस्खलन की चपेट में आने से मकान और होटल ढह गए। होटल में ठहरे म्यांमार के कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि घटना की विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। पूर्वोत्तर राज्य में शुक्रवार से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाएं हुई हैं। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बीते 48 घंटे से हो रही भारी बारिश के चलते असम सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आकस्मिक छुट्टी घोषणा कर दी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी परामर्श में कहा गया कि तेज बारिश ने राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से के जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बने दबाव के कारण इन जिलों में 20-30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है।

ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी भारत की नारी शक्ति की ताकत

नई दिल्ली।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की रक्षा क्षमताओं का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। लेकिन साथ ही भारतीय सैन्य बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और अग्रिम मोर्चे पर उनकी क्षमता को विश्व ने देखा है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नारी शक्ति की सराहना कर कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में महिला पायलटों ने पाकिस्तान में ठिकानों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गोवा में आईएनएसवी तारिणी के फ्लैग-इन समारोह को संबोधित राजनाथ सिंह ने कहा कि जब से सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, उन्होंने हर भूमिका में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खुले हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी से 17 महिलाएं पास आउट हुई हैं।

रक्षा मंत्री सिंह ने गोवा में दो महिला नौसेना अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए की भी सराहना की, जो नाविका सागर परिक्रमा सेंकड के सफल समापन के बाद घर आई हैं।

बता दें कि इन दोनों महिला अधिकारियों ने आठ महीनों में 25,600 समुद्री मील की दूरी तय की, जिसमें फेमेंटल (ऑस्ट्रेलिया), लिटलेटन (न्यूजीलैंड), पोर्ट स्टेनली (फॉकलैंड द्वीप समूह) और केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका) में पोर्ट कॉल किए गए।

वहीं बीएसएफ की सहायक कमांडेंट नेहा भंडारी ने जवानों का नेतृत्व कर 'जीरो लाइन' के पार शत्रु की तीन अग्रिम चौकियों को मुंहतोड़ जवाब देकर खामोश कर दिया था। नेहा के अलावा छह महिला कांस्टेबल अग्रिम सीमा चौकी पर बंदूक थामे थीं और सांबा-आर एस पुरा-अखनूर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार दुश्मन के ठिकानों पर दागी गई हर गोली के साथ उनका जोश बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा, ''मेरे साथ 18 से 19 महिला सीमा रक्षक थीं। छह महिलाएं निगरानी चौकियों पर पर गोलीबारी का जवाब दे रही थीं। हमें उन पर गर्व है।''

अग्रिम चौकियों पर महिलाओं की भूमिका और पाकिस्तानी चौकियों पर गोलीबारी में उनकी भागीदारी की प्रशंसा कर बीएसएफ के महानिरीक्षक शशांक आनंद ने कहा, ''बीएसएफ की महिलाकर्मियों ने ऑपरेशन में शानदार भूमिका निभाई। हालांकि उनके पास बटालियन मुख्यालय में जाने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने अपने पुरुष समकक्षों के साथ अग्रिम चौकियों पर ही रहने का फैसला किया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया।

एनडीए का नया रिकॉर्ड

दूसरी ओर, पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) से

स्नातक 17 महिला कैडेट के पहले बैच ने 300 से अधिक पुरुष कैडेट के साथ 'पासिंग आउट परेड' में हिस्सा लेकर इतिहास रच दिया। एनडीए में पुरुष और महिला कैडेट का यह पहला सह-शिक्षा बैच है। कैडेट खड़कवासला में त्रि-सेवा प्रशिक्षण अकादमी के खेत्रपाल परेड ग्राउंड में 'अंतिम पग' से गुजरे, जिसे व्यापक रूप से ''नेतृत्व का उद्गम स्थल'' के रूप में जाना जाता है।

पहला कॉलम

सीडीएस ने माना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का लड़ाकू विमान भी नष्ट हुआ

पाकिस्तान के राफेल सहित छह विमानों को मार गिराने के दावे को खारिज किया

नई दिल्ली।

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के एक के बाद एक दावों की पोल खुलने लगी। लेकिन इसके बीच पाकिस्तान द्वारा एक ऐसा दावा किया गया था, इसपर भारतीय पक्ष से अब तक कोई जवाब नहीं आया था। पाकिस्तान का दावा था कि भारत के पांच फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। अब इसके जवाब में भारत ने पहली बार इसकी पुष्टि की है। उन्होंने स्वीकारा किया हैं कि भारत का लड़ाकू विमान भी इसमें नष्ट हुआ है। हालांकि सीडीएस अनिल चौहान ने बताया कि कभी भी परमाणु युद्ध की नौबत नहीं आई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल चौहान पहले भारतीय अधिकारी बन गए हैं जिन्होंने पुष्टि की है कि 7 मई को पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारतीय वायुसेना ने कुछ लड़ाकू विमान गंवाए हैं। सिंगापुर में एक साक्षात्कार में हालांकि उन्होंने उस रात भारत द्वारा खोए गए लड़ाकू विमानों की सटीक संख्या बताने से इंकार किया। जनरल चौहान ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि विमान गिरा, बल्कि यह है कि वे क्यों गिराए गए। लड़ाकू विमानों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा वे क्यों गिरे, क्या गलतियाँ हुईं, यही महत्वपूर्ण है। संख्याएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान के उन दावों को भी बिल्कुल गलत बताया कि छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। दरअसल आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और वायु संचालन महानिदेशक एयर मार्शल एके भारती ने नुकसान से इंकार नहीं किया था। भारती ने कहा था कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान युद्ध का एक हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कोई भी विवरण देने से इंकार कर दिया। जनरल चौहान नुकसान की पुष्टि करने वाले पहले अधिकारी बन गए हैं। सीडीएस ने बताया कि भारत ने उन नुकसानों से सबक सीखा है और संघर्ष के दौरान उन्हें लागू किया है। इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि उनके देश ने संघर्ष की पहली रात को तीन फ्रांसीसी राफेल सहित छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था।

दिल्ली को जल्द मिलेगा नया राज्यपाल, मनोह सिन्हा की होगी पार्टी संगठन में वापसी

नई दिल्ली।

दिल्ली को जल्द ही एक नया उपराज्यपाल (एल-जी) मिलने की संभावना बन रही है। केंद्र कथित तौर पर राज्यपालों के पदों में फेरबदल पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के एलजी के लिए तीन नामों अजय भल्ला, राजेश खुल्लर और सी वी आनंद बोस के नाम प्रमुख है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के मौजूदा एलजी वीके सक्सेना को जम्मू-कश्मीर या बंगाल भेजा जा सकता है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को कथित तौर पर पार्टी संगठन में लाने पर विचार कर रही है। एक भाजपा नेता ने कहा कि सिन्हा सबसे अच्छे चुनावी रणनीतिकारों में से एक हैं और एक सख्त टास्कमास्टर हैं। पार्टी प्रमुख के पद के लिए उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल भल्ला, सक्सेना की जगह लेने के लिए सबसे आगे हैं, उनके बाद पूर्व आईएएस अधिकारी खुल्लर का नाम है। दिल्ली में प्रशासनिक भूमिकाओं में अपने अनुभव के कारण भल्ला को यह पद दिया जा रहा है हालांकि, मणिपुर में सरकार बनने के बाद ही भल्ला दिल्ली में वापसी कर सकते है। ऐसी खबरें हैं कि सरकार पूर्वोत्तर मामलों को संभालने का अनुभव रखने वाले किसी पूर्व आईएएस या आईपीएस अधिकारी को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त कर सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के सीजफायर कराने वाले राग को भारत ने सिरे से किया खारिज

नई दिल्ली।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को पूर्ण संघर्षविराम, संभवतः परमाणु टकराव होने से रोका है। ट्रंप ने कहा कि हमने व्यापार पर बात की और हमने कहा कि हम उन लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो एक-दूसरे पर गोली चला रहे हैं और संभावित रूप से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। उनके पास में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क बैठे थे, जो ट्रंप प्रशासन में सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका से हट रहे हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि जिस ''सौदे'' पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व है, वह भारत और पाकिस्तान के बीच ''संभावित परमाणु युद्ध को गोलियों के बजाय व्यापार'' के जरिए से रोकने में सफल रहना है। ट्रंप ने पिछले कुछ हफ्तों में कई बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया। उन्होंने कहा कि अगर वे संघर्ष नहीं रोकेंगे तो अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार बंद कर देगा। भारत ने गुरूवार को कहा था कि पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच बातचीत में व्यापार के मामले पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। भारत ने अमेरिका के इस दावे को खारिज किया है कि व्यापार संबंधी उसके प्रस्ताव के कारण संघर्ष रोकने पर सहमति बनी है। ट्रंप ने शुक्रवार को फिर वही दावा दोहराया। ट्रंप ने कहा कि आमतौर पर वे गोलियों के जरिए से ऐसा करते हैं। हम व्यापार के जरिए से ऐसा करते हैं, इसलिए मुझे इस पर बहुत गर्व है। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच एक बहुत ही भयानक संभावित युद्ध हो रहा था। अब यदि आप देखें तो वे सही दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत बुरा होता जा रहा था। वे दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि अगले सप्ताह अमेरिका आ रहे हैं। ट्रंप ने 'एयर फोर्स वन' से निकलने के बाद कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत के साथ सौदा करने के बहुत करीब हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर वे एक-दूसरे के साथ युद्ध करते हैं तो मुझे उनमें से किसी के साथ सौदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं उन्हें बता दूंगा। यह एक दिन में दूसरी बार है जब ट्रंप ने अपना यह दावा दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीजफायर करवाया। ट्रंप ने कहा कि वह ''भारत और पाकिस्तान के नेताओं और अपने लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के नेता ''महान'' हैं और ''उन्होंने समझदारी दिखाते हुए सहमति जताई जिसके बाद यह सब बंद हो गया। ट्रंप ने कहा कि हम दूसरों को भी लड़ने से रोक रहे हैं क्योंकि आखिरकार हम किसी से भी बेहतर लड़ सकते हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है।

भारत का जिगरी दोस्त रूस पाकिस्तान में करेगा करोड़ों निवेश...क्या पीट में छुरा घोपा

नई दिल्ली।

पाकिस्तान और चीन के संबंध कैसे हैं। इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन अब पाकिस्तान की मदद के लिए एक ऐसा देश सामने आया है, जो भारत का सबसे अच्छा दोस्त हैं। रूस का ये कदम भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। दरअसल, रूस के सहारे पाकिस्तान की सरकार अपने उद्योग को फिर से पटरी पर लाने का काम कर रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच रूस ने पाकिस्तान के साथ एक अहम आर्थिक समझौता किया है। अरबों डॉलर के सौदे के तहत कराची में एक आधुनिक स्टील प्लांट बनाया जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य सोवियत निर्मित पाकिस्तान स्टील मिल्स (पीएसएम) को पुनर्जीवित करना है, जो 2015 से बंद है। इस सौदे की अनुमानित लागत 2.6 बिलियन डॉलर (करीब 22,000 करोड़ रुपये) है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। यह प्लांट 1970 के दशक में सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था। यह 1992 तक चालू रहा, लेकिन आर्थिक और तकनीकी कारणों से 2015 में बंद कर दिया गया। नए समझौते के तहत रूस उन्नत स्टील निर्माण तकनीक यानी स्टील उत्पादन के लिए सबसे उन्नत तकनीक वाली मशीनें मुहैया कराएगा, जिससे पाकिस्तान की स्टील आयात पर निर्भरता 30 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है। इस परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान के 11.2 मिलियन मीट्रिक टन स्टील खपत घाटे को कम करना है। मार्च 2025 में आयातित स्क्रैप और अर्ध-तैयार उत्पादों की लागत 324 मिलियन डॉलर थी। इस डील से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्टील के आयात में 30 प्रतिशत की कमी से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा, जो पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रूस की उन्नत स्टील निर्माण तकनीक का उपयोग करके, पाकिस्तान का स्टील उद्योग आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनेगा। **भारत के लिए चिंता की बात है?** यह समझौता भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच हुआ है, जिससे भारत में इस डील को लेकर चिंताएं हैं। रूस हमेशा से भारत को अपना रणनीतिक साझेदार मानता रहा है, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया संतुलित और तटस्थ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले की निंदा की, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों से तनाव कम करने का आह्वान किया और मध्यस्थता की पेशकश भी की।

एनएचएआई की जमीन पर अतिक्रमण कर किराए पर दी, कोर्ट भी हैरान

हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज, मामले को बताया अनूठा मामला

प्रयागराज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जमीन पर वक्फ मदरसा द्वारा निर्माण कराकर उसे किराए पर देने पर आश्चर्य जताया है। यह बताए जाने पर कि याचिकाकर्ता वक्फ ने एनएचएआई की भूमि पर अतिक्रमण किया है, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वक्फ की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने इस मामले को एक ÷अनूठा मामला÷ बताया, जहां एनएचएआई की जमीन पर अतिक्रमण करके मदरसा और कुछ अन्य निर्माण किए गए और इस संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। वक्फ ने विवादित संपत्ति को ध्वस्त करने से प्रतिवादियों को रोकने और किसी नए निर्माण पर रोक लगाने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उस जमीन पर एक मदरसा, मस्जिद और एक पुलिस चौकी पहले से मौजूद थी। याचिकाकर्ता के इस दावे के संबंध में वह भूमि वक्फ की संपत्ति है, प्रतिवादियों ने कहा कि यह संपत्ति वक्फ के तौर पर वक्फ बोर्ड में पंजीकृत नहीं है। प्रतिवादियों ने मामले में एक संशोधन याचिका दायर की, जिसे निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका दायर की, जो खारिज कर दी गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा कि संशोधन की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि प्रतिवादी इसके

जरिये एक नया वाद खड़ा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने किसी भी स्तर पर वक्फ का पंजीकरण नहीं दिखाया और यह नहीं बताया कि कैसे वह संपत्ति, वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत वक्फ संपत्ति है। कोर्ट ने कहा कि वह एनएचएआई की संपत्ति है और निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह आदेश 12 मई का है, जिसे शुक्रवार को अपलोड किया गया था।

असम में देशद्रोहियों के खिलाफ एक्शन जारी, पाकिस्तान प्रेमी की गिरफ्तारी

इस तरह गिरफ्तारियों की कुल संख्या 79 हो गई

डिसपुर।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत रखने के आरोप में राज्य में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस तरह गिरफ्तारियों की कुल संख्या 79 हो गई है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान दरांग जिले के मंगलदाई निवासी फरीज-उल हक के रूप में हुई है। सीएम सरमा ने कहा, पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 79 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीएम शर्मा ने पहले कहा था कि देशद्रोहियों पर राज्यव्यापी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जो कथित तौर पर ''भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों'' में लिप्त हैं।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गगनयात्री कैप्टन शुक्ला करेंगे ये प्रयोग

सलाद के बीजों का अंतरिक्ष में उगना अहम

नई दिल्ली।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के गगनयात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के आगामी मिशन को लेकर बड़ा बयान दिया है।

रिपोर्ट में बताया गया कि वे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण से जुड़े प्रयोग करुंगा। इसरो के अनुसार, 7 माइक्रोग्रैविटी प्रयोगों का चयन हुआ है। ये विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों के भारतीय शोधकर्ताओं की ओर से प्रस्तावित किए गए हैं। ये प्रयोग मानव स्वास्थ्य, जीव विज्ञान, मेटरियल रिसर्च, नई दवाओं के विकास और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। रिपोर्ट के मुताबिक, 8 जून को शुरू होने वाले मिशन में शुभांशु शुक्ला कई तरह के प्रयोग करने वाले हैं।

इसमें माइक्रोएल्गी पर अंतरिक्ष के विकिरण का असर और सलाद के बीजों का अंतरिक्ष में उगना अहम है। साथ ही, टार्डिग्रेड नाम के छोटे जीवों की अंतरिक्ष में जीवित रहने और प्रजनन की क्षमता, मांसपेशियों के विकास पर पूरकों का प्रभाव और खाद्य फसलों के बीजों की वृद्धि का भी आकलन किया जाएगा। इन सारे प्रयोगों में आईएसएस की सुविधाओं का इस्तेमाल होगा और इन्हें सख्त जांच के बाद ही वहां ले जाया जाएगा।

देश में 500 और 200 के नकली नोट के बढ़ने से चिंतित आरबीआई

नई दिल्ली।

देश में नकली करेंसी का खतरा फिर बढ़ रहा है, खासकर 500 और 200 के नोटों को लेकर चिंता बढ़ी है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में सामने आया है कि 500 के नकली नोटों की संख्या में 37.3 प्रतिशत और 200 के नकली नोटों में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि में कुल 2,17,396 नकली नोट पकड़े गए, जो कि बीते कुछ वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक, नकली नोटों का बड़ा हिस्सा निजी बैंकों द्वारा पकड़ा गया है, जबकि केवल 4.7 प्रतिशत नोट आरबीआई की निगरानी में आए हैं। यह दिखाता है कि नकली नोट आम बैंकिंग लेन-देन के जरिए बाजार में आ रहे हैं, जिससे आम जनता के लिए सतर्क रहने की जरूरत है।

500 के नकली नोटों की कुल संख्या 1,17,722 है,जबकि 200 के नकली नोट 32,660 पकड़े हैं। कुल नकली नोटों की संख्या 2022-23 के 2,25,769 से कुछ कम होकर 2024-25 में 2,17,396 रह गई है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय है कि 500 और 200 के नोटों में नकली नोटों की संख्या में वृद्धि हुई है। नकली नोटों के इस बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए आम लोगों को खुद भी सतर्क रहना होगा और नोटों की जांच करने की आदत डालनी होगी। असली 500 नोट की पहचान करने के लिए कुछ खास बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे इसका रंग स्टोन ग्रे होता है, आकार 66 मिमी × 150 मिमी है, और इसमें महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ देवनागरी में '500' लिखा होता है। सिक्योरिटी थ्रेड रंग बदलने वाला होता है जो हरे से नीले रंग में बदलता है। इसके अलावा नोट में गांधी जी की वॉटरमार्क छवि और '500' अंकित होता है। नोट के पीछे लाल किले की तस्वीर होती है। वहीं 200 के नोट का रंग ब्राइट येलो

है, आकार 66 मिमी ×146 मिमी है, और इसमें भी गांधी जी की तस्वीर के साथ देवनागरी में '200' अंकित होता है। इसके पीछे सांची स्तूप की छवि और स्वच्छ भारत का लोगो मौजूद है। रिपोर्ट बताती हैं कि नकली नोट पकड़ने और इसके प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना बेहद जरुरी है। अगर किसी के पास शक के तहत नोट हो, तब उसे बैंक में जांच कराना ही सबसे सही कदम होगा। नकली नोटों से बचाव और पहचान के लिए यह जानकारी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्न का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717